किसान आत्महत्या : एक अभिसाप

डॉ0 अजय प्रकाश भारती*

भारत एक कृषि प्रधान देश कहा जाता है क्योंकि यह देश एक कृषि आधारित अर्थव्यवस्था हैं लगभग श्रमिक आबादी का लगभग दो तिहाई भाग प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से कृषि पर निर्भर हैं हालांकि देश के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि एवं उससे जुड़े हुए क्षेत्रों का योगदान विगत कई वर्षो से गिरता जा रहा है (वर्ष 1950–51 में 51.9 प्रतिशत से 2012–13 में 13.7 प्रतिशत रह गया) इकॉनामिक टाइम्स, अगस्त 30, 2013 अपनी राजनीतिक स्वतन्त्रता प्राप्त करने के मात्र कुछ दशकों के अन्दर ही भारत ने खाद्यान्नों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल कर ली है। देश का खाद्यान्न उत्पादन वर्ष 1951–52 के 5.2 करोड़ टन से बढ़कर वर्ष 2011–12 में 25.7 करोड़ टन से अधिक हो गया।

कृषि क्षेत्र में संकट 1990 के दशक से प्रारम्भ हुआं आर्थिक सुधारों के समय से राष्ट्रीय नीति ने कृषि व्यवस्था को हाशिए पर डाल दिया गया। ऋणग्रस्तता भी कृषि क्षेत्र में संकट का एक कारण है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) के द्वारा संपन्न किये गये एक सर्वेक्षण के 59वें चक्र के एक भाग के अनुसार भारत के किसानों में से लगभग आधे ऋणग्रस्त हैं। भारत में कृषि से संलिप्त 89.35 मिलियन ग्रामीण परिवारों में से 43.42 मिलियन अर्थात् 48.6 प्रतिशत लोग कर्ज में डूबे हुए हैं।

भारत में किसानों की आत्महत्या की शुरूआत 1990 के दशक में चिंता का कारण बन गई। एक हिन्दू अखबार के पत्रकार पी0 साईनाथ ने सबसे पहली बार आत्महत्याओं की एक बड़ी संख्या को उजागर किया। सबसे पहला राज्य जहाँ आत्महत्या की सूचना दी गयी थी, वह महाराष्ट्र था। इसके बाद धीरे–धीरे आन्ध्रप्रदेश के समाचार पत्रों में भी रिपोर्ट देना शुरू कर दिया। जबकि पहली सरकारी रिपोर्ट में इनसे इन्कार किया गया था। लेकिन जैसे–जैसे यह मामले भारी संख्या में बढ़ते गये तब जाकर सरकार ने यह स्वीकार करना प्रारम्भ कर दिया कि किसान बहुत ज्यादा तनाव में हैं।

शुरूआत में ऐसा माना जा रहा था कि आत्महत्या में अधिकांश कपास उपजाने वाले किसानों के बीच हो रही है, खासकर विदर्भ के किसानों के बीच। राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो के द्वारा उपलब्ध कराये गये आँकड़े यह संकेत देने के लिए पर्याप्त थे कि ऐसा कपास के किसानों के बीच नहीं था बल्कि एक पेशावर वर्ग के रूप में पीड़ित किसानों के साथ हो रहा था, भले ही उनकी जोत का आकार कुछ भी रहा हो। इसके अलावा यह मात्र विदर्भ के ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण महाराष्ट्र के किसान थे, जिन्होंने आत्महत्या की महत्वपूर्ण रूप से ऊँची दर का प्रदर्शन किया था। सरकारी आँकड़ों के अनुसार सन् 2002 एवं 2006 के बीच प्रतिवर्ष 17500 किसानों ने स्वयं को मार डाला था। महाराष्ट्र के अलावा अन्य राज्यों जहाँ आत्महत्याएँ की गयीं उनमें महाराष्ट्र, आध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल एवं पंजाब राज्य शामिल थे। राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो (एनसीआरबी) के अनुसार सन् 2006 में महाराष्ट्र राज्य 4453 किसान आत्महत्याओं के साथ 17060 के अखिल भारतीय योग के एक चौथाई भाग का भागीदार था।

* **लखनऊ**

एनसीआरबी ने यह भी उल्लेख किया था कि सन् 2008 में भारत में कम से कम 16196 किसानों के द्वारा आत्महत्याएँ की गयीं। जो सन् 1997 से अभी तक के योग को 199132 तक पहुँचा देता है। सरकारी आँकड़ों के अनुसार 5000 से भी अधिक किसानों ने सन् 2005 एवं सन् 2009 के बीच महाराष्ट्र में आत्महत्याएँ कीं। जबकि 1313 मामलों की सूचनाएँ सन् 2005 एवं 2007 के बीच आन्ध्र प्रदेश से प्राप्त हुईं थीं।

कर्नाटक में वर्ष 2005–06 से अगस्त 2009 तक यह संख्या 1003 पर थी। एनसीआरबी के आँकड़ों के अनुसार गुजरात में वर्ष 2005–09 के दौरान आत्महत्याओं की संख्या 387 थी। जबकि केरल में यह 905, पंजाब में 75 तथा तमिलनाडु में 26 थी। अप्रैल 2009 में छत्तीसगढ़ राज्य में ऋण एवं फसल खराब होने के कारण 1500 किसानों के द्वारा आत्महत्या किये जाने की सूचना दी थी। सन् 2009 में कम से कम 17368 भारतीय किसानों ने आत्महत्या की थी। जो कि विगत 6 वर्षों में सबसे ज्यादा आँकड़ा है।

आत्महत्या के कारण

शोध के अध्ययन से आत्महत्याओं के विभिन्न कारणों की पहचान की गयी। कृषि ऋणग्रस्तता को इसके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण के रूप में उद्धृत किया गया। बढ़ती हुई लागते एवं कम लाभों की स्थिति में ही संस्थागत ऋणों में आती हुईं कमियाँ तथा शोषण कार्य अनौपचारिक कर्ज के जाल किसानों के बीच व्यापक होती हुई ऋणग्रस्तता का कारण रहे हैं। सन् 2003 में एनएसएसओ में 59वें चक्र में किसानों की स्थिति निर्धारण सर्वेक्षण से यह स्पष्ट हुआ कि देश के लगभग आधे किसान ऋणग्रस्त हैं। यही प्रवृत्ति पंजाब हरियाणा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल एवं कर्नाटक जैसे लागत प्रधान कृषि वाले राज्यों में अधिक थी। आन्ध्रप्रदेश में सर्वाधिक 82 प्रतिशत थी।

मद्रास विकास अध्ययन संस्थान के के0 नागराज ने यह स्पष्ट किया हे कि 90 के दशक के मध्य के बाद से आगे की कीमतें एवं कृषि आय धाराशायी हो गयी। जैसे–जैसे लागत बढ़ती गयी यहाँ तक कि बैंक ऋण भी कम होते गये वैसे–वैसे ऋणग्रस्तता भी बढ़ती गयी जहाँ पश्चिम में निगमित किसानों के लिए सब्सिडियों में कटौती कर दी गयी। कृषि में निवेश समाप्त होने का अर्थ यह था कि इस जाल से बाहर निकल पाना सबसे कठिन था।

मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग के अनुसार ऋणग्रस्तता ही किसानों के बीच आत्महत्या का एकमात्र कारण नहीं रहा है। किन्तु कम से कम 20–25 अन्य बाध्यकारी कारण भी मध्य प्रदेश में सैकड़ों किसानों को स्वयं जान लेने के लिए प्रेरित कर रहे हैं (टाइम्स ऑफ इण्डिया, दिसम्बर 11, 2011) सत्यनारायण एवं संजय (2014 के द्वारा) किये गये पंजाब के एक अन्य अध्ययन से यह स्पष्ट हुआ कि अकेला ऋण ही आत्महत्याओं का पर्याप्त शर्त नहीं है, किन्तु ऋण की वसूली की प्रक्रिया तथा नियामक समर्थन एवं अहंकारी प्रवृत्तियाँ भी पर्याप्त कारणों के रूप में पायी गयीं हैं।

संयुक्त परिवार के महत्व पर बल देते हुए आर0एस0 देशपाण्डेय जोर देते हैं कि संयुक्त परिवार प्रणाली में प्रत्येक सदस्य सुरक्षित था। पुराने दिनों में संयुक्त परिवार संकट के समय में अपने सदस्यों को नैतिक समर्थन प्रदान किया करते थे। आत्महत्या करने वाले अधिकांश किसान एकल परिवारों से आते हैं। यहाँ तक कि अपने स्मरणीय योगदान सुसाइड में ईमाइल डरखाइम उस सह–सम्बन्ध के बारे

में बतलाते हैं जो परिवार के आकार तथा आत्महत्या की घटनाओं के बीच विद्यमान है। उनके अनुसार ''परिवार के आकार तथा आत्महत्या की प्रवृत्ति के बीच एक विपरीत सम्बन्ध विद्यमान है''।

डरखाइम लिखते हैं कि–कोई भी व्यक्ति लगातार पारिवारिक वातावरण के परोपकारी अनुशासन के अधीन रहने की तुलना में अकेले तथा स्वयं के लिए छोड़ दिये जाने पर नैतिक तौर पर लगभग निश्चित तौर पर अधिक आश्वस्त होता है। देशपांडे यह भी कहते हैं कि–सामाजिक संस्थाओं की उन लोगों जो टूटन की कगार पर हैं, के बीच आत्मविश्वास भरने एवं स्थापित कर पाने की विफलता किसानों के बीच आत्महत्या के प्रमुख उत्तरदायी कारणों में से एक रही है।

कहीं–कहीं पर सूखा पड़ना भी किसानों के आत्महत्या करने पर प्रमुख कारण रहा है। भारत में कृषि लगभग मानसून पर ही निर्भर है, क्योंकि देश की 80 प्रतिशत कृषि भूमि मानसून के मौके दौरान आने वाली वर्षा पर ही निर्भर है, अतः अपर्याप्त वर्षा सूखे का कारण हो सकती है, जो फसल को विफलता को कहीं अधिक आम बात बना देती है। ऐसे क्षेत्रों में जिनके द्वारा सूखे का अनुभव किया जा चुका है, फसल की उपज में गिरावट आ चुकी है तथा पशुओं के लिए भोजन दुर्लभ हो गया है। कृषि से जुड़े ऐसे क्षेत्रों, जो सूखे से प्रभावित हो चुके हैं, के द्वारा इसके परिणाम–स्वरूप अपनी आत्महत्याओं की दरों में वृद्धि होते हुए देखा गया है।

रोकथाम एवं रणनीतियाँ

भारी मात्रा में किसानों के आत्महत्या करने के परिणामस्वरूप केन्द्र सरकार तथा संबन्धित राज्य सरकारों ने तनावों से निपटने के लिए उपाय की घोषणा कर दी, लेकिन इसके बावजूद भी किसान आज भी आत्महत्या कर रहे हैं, लगभग भारत के सभी राज्यों से इस प्रकार की सूचनाएँ अक्सर मिलती रहती हैं। वास्तव में कृषि में व्यवस्थित जोखिम कुछ दशकों पहले की तुलना में आज गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों ही रूप से अलग–अलग हो चुका है। बढ़ता हुआ व्यवशायीकरण तथा आगतों से भारी निवेश के साथ–साथ तकनीकों एवं पारंपरिक मौसम के जोखिम के साथ ऋण सम्बन्धी जोखिम। इसके साथ ही उदारवाद ने बाजार सम्बन्धी जोखिमों को भी जोड़ दिया है। इन सब के 90 के दशक के समय से राज्य से घटते हुए समर्थन के द्वारा बल प्रदान किया गया है।

कुछ लोगों ने किसान समुदायों के बीच आत्महत्या को प्रभावी रूप से कम करने के लिए कुछ उपाय बताए हैं जिसमें से एक वंदना शिवा का कहना है कि–किसानों द्वारा आत्महत्या को रोकने सम्बन्धी रणनीति में जीएमओ से एक स्थानांतरण तथा जैविक के लिए गैर नवीनीकरणीय बीजों, खुले परागकृत बीज की किस्मों, जिसे किसान बचा एवं साझा कर सकते हैं, रासायनिक खेती से जैविक खेती की ओर तथा गलत मूल्यों पर आधारित अनुचित व्यापार से वास्तविक एवं उचित मूल्यों पर आधारित व्यापार की ओर किया जाने वाला परिवर्तन आदि को शामिल किया जा सकता है और जिन किसानों ने ऐसा परिवर्तन कर लिया है, वे आज मोनसैटों के बीती–कपास के उत्पादन करने वाले किसानों की तुलना में 10 गुना अधिक आय अर्जित कर रहे हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. Durkheim, Emile, *Suicide : A study in sociology*, Tr John A, Spoulding and George Simpsons, London: Routledge and kegon Paul.
2. Mishra, Srijit, *"Risks, Farmern' suicides and Agrarian Crisis in India is There a way out?"* Mambai: Indira Gandhi Institute of Development REsearch, Working Paper 2007-14, September 2007.
3. Posani, Balamaralidhar, *"Cirsis in the countryside: Farmer suisides and the Political Economy of Agrarian Distress in India"*. Working Paper 09-95, Development stuies Institute, London School of Economics and Political Science, 2009.
4. आहूजा, राम ए सामाजिक समस्याएँ रावत पब्लिकेशन्स, कृषि संकट और आत्महत्या.